मोदी सरकार रोजगार के छद्म आंकड़ों को प्रोत्साहित कर रही है जिनका परीक्षण नहीं हुआ

मौजूदा सरकार अपने हितों को साधने के लिए औपचारिक क्षेत्र के रोजगार के उन आंकड़ों को प्रोत्साहित कर रही है जिनका परीक्षण नहीं हुआ और जो पहले के मानकों के उलट है। 25 अप्रैल, 2018 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ, ईएसआईसी और पीएफआरडीए ने पेरॉल के आधार पर रोजगार के आंकड़े जारी किए। ये आंकड़े कर्नाटक चुनाव के एक पखवाड़ा पहले जारी किए गए। ऐसे ही बजट के पहले भी मध्य जनवरी में आंकड़े जारी किए गए थे। इस अध्ययन के लिए ईपीएफओ, ईएसआईसी और राष्ट्रीय पेंशन योजना के प्रशासनिक आंकड़ें लिए गए थे। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने इन आंकड़ों के आधार पर दावा किया कि 2017-18 में 70 लाख नए रोजगार पैदा हुए।

जनवरी के आंकड़ों के बाद जो कहा गया था, उसे याद दिलाना जरूरी है: ये अनुमान सिर्फ ये बताते हैं कि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कितना लाभ ले रहे हैं। इनमें कुछ ऐच्छिक हैं जैसे ईएसआईसी। वहीं ईपीएफओ अनिवार्य है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस अनिवार्य है। लेकिन राज्य सरकारों और निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए यह ऐच्छिक है। ईपीएफओ भी उन्हीं संगठनों के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जो कुछ शर्तों को पूरा करती हों।

सितंबर, 2017 से फरवरी, 2018 के बीच 32.7 लाख ईपीएफओ खाते खुले वहीं 4.2 लाख लोग एनपीएस में शामिल हुए। इनमें से 25 साल से कम उम्र वालों के ईपीएफओ खातों की संख्या 20.5 लाख और ऐसे एनपीएस वालों की संख्या 84,659 रही। ईएसआईसी खातों की संख्या सितंबर, 2017 के 2.9 करोड़ से घटकर फरवरी, 2018 में 2.7 करोड़ रह गई। ईएसआईसी के आंकड़ों के आधार पर कोई विश्लेषण करना ठीक नहीं है क्योंकि इसमें काफी बदलाव होते रहते हैं। यहां तक की ईपीएफओ के आंकड़ों में भी यह फर्क कर पाना आसान नहीं है कि कितने खाते नए रोजगार पाने वालों के हैं और कितने नए खातों रोजगारों के औपचारिक होने की वजह से खुले हैं। अगर ईपीएफओ और एनपीएस के आंकड़ों को सही मान भी लिया जाए तो कुल नए रोजगारों की संख्या छह महीने में 21 लाख ही होती है और एक साल में 42 लाख। यह 70 लाख के दावे से काफी कम है।

देश में कुल श्रमिकों की संख्या में औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या 10 फीसदी से भी कम है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि 90 फीसदी श्रमिक बाजार में रोजगार की स्थिति जस की तस रही। हालांकि, वास्तविक आंकड़ों के आधार इनमें से किसी अनुमान को सही नहीं कहा जा सकता। नैशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के 2004-05 से 2011-12 के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ कृषि क्षेत्र में हर साल 50 लाख रोजगार कम हुए। यह पेरॉल के जरिए रोजगार सृजन के आंकड़ों से काफी अधिक है। श्रम ब्यूरो के हालिया सर्वेक्षणों के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र में रोजगार और कम हुए हैं। नोटबंदी और जल्दबाजी में लागू किए गए जीएसटी से स्थितियां और खराब हुई हैं।

असल काम यह होना चाहिए कि नियमित तौर पर घरों का सर्वेक्षण हो। 2004 से 2011 के बीच एनएसएसओ ने रोजगार संबंधित छह वार्षिक सर्वे किए थे। इनमें से चार बड़े सैंपल सर्वे थे। 60वें चक्र के सर्वेक्षण में सालाना रोजगार के आंकड़े मिल रहे थे। लेकिन ऐसे सर्वेक्षण को 2011-12 से बंद कर दिया गया। ऐसे ही श्रम ब्यूरो के घरेलू सर्वेक्षण को भी बंद कर दिया गया। दूसरे कई सर्वेक्षण में यह बात आई है कि पिछले तीन साल में पहले के सरकार के कार्यकाल के मुकाबले कम रोजगार पैदा हुए हैं। एनएसएसओ ने पहले शहरी और बाद में ग्रामीण क्षेत्र के लिए तिमाही सर्वेक्षण की शुरुआत की है लेकिन इसके आंकड़े 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

पेरॉल आंकड़ों के आधार पर चले रहे विमर्श को व्यापक तौर पर देखना होगा। पिछले एक दशक में सात फीसदी की अधिक विकास दर के बावजूद अर्थव्यवस्था में अपेक्षित रोजगार नहीं पैदा हो रहे हैं। गांवों और शहरों के अधिकांश नौजवान बेरोजगार हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। इनमें कृषक समुदाय से आने वाले जाट, मराठा और पटेल शामिल हैं। इन युवाओं के लिए सच्चाई सरकारी दावों से उलट है। आंकड़ों की बाजीगरी से कम समय के लिए चुनावी मुद्दा तो मिल जाता है लेकिन रोजगार सृजन के लिए बेहतर नीतियों के निर्धारण में इससे कोई मदद नहीं मिलती।

अब भाजपा के वरिष्ठ नेता बोले, टेस्ट ट्यूब बेबी थीं माता सीता

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बोले, माता सीता टेस्ट ट्यूब तरीके से पैदा हुई संतान थीं, सीता जी का जन्म घड़े की मदद से हुआ था, जो उस वक्त टेस्ट ट्यूब से बच्चे पैदा करने का एक तरीका था...

भाजपा नेताओं के एक के बाद एक जिस तरह ज्ञान चक्षु खुलते जा रहे हैं, उससे लगता है उन्हें इस युग में पैदा होना ही नहीं चाहिए था। विवादास्पद और विज्ञान को चुनौती देने वाले नेताओं में एक और भाजपाई की एंट्री हो गई है।

विवादित बयानों और विज्ञान को चुनौती देते दावे पेश करने में भाजपा नेताओं का कोई सानी नहीं है। अब इस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का, जिनके मुताबिक रामायण की नायिका सीता टेस्ट ट्यूब बेबी थीं।

उत्तर प्रदेश के भाजपा उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने यह कहकर सनसनी फैलाने का काम किया है कि सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी थीं। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कल 31 मई को %इंडिया स्किल्स क्षेत्रीय प्रतियोगिता-2018% के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए दिनेश शर्मा ने यह बातें कहीं। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में पांच राज्यों के दो सौ से अधिक प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। बच्चों को ज्ञान बांटने वाले उप मुख्यमंत्री यहीं नहीं थमे, उन्होंने कहा कि यहां से निकलने वाले बच्चे विदेशों में जाकर भारत का परचम लहराएंगे। इन सबके पीछे भारत के प्रधानमंत्री की सोच है। तो यह मान लिया जाए कि स्किल इंडिया के तहत प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए बच्चे भी कुछ इसी तरह का ज्ञान विदेशों में प्रचारित कर भारत को जगहंसाई का पात्र बनाएंगे।

हालांकि जरूर यह मोदी जी की ही मुहिम होगी, क्योंकि मोदी खुद भी हिंदुओं के पूजनीय गणेश जी को प्लास्टिक सर्जरी का सबसे अच्छा उदाहरण सार्वजनिक सभा के दौरान बता ही चुके हैं, जाहिर सी बात है बाकी नेता भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आज के दौर से रामायण काल को बेहतर बताते हुए कहा, माता सीता टेस्ट ट्यूब तरीके से पैदा हुई संतान थीं। सीता जी का जन्म घड़े की मदद से हुआ था, जो उस वक्त टेस्ट ट्यूब से बच्चे पैदा करने का एक तरीका था।

गौरतलब है कि कल 31 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी था, इसलिए वो यह भी कहने से नहीं चूके कि पत्रकारिता कोई आधुनिककाल से शुरू नहीं हुई थी, यह महाभारत काल से चली आ रही है। इस दौरान दिनेश शर्मा ने यह भी दावा किया कि गुरुत्वाकर्षण बल, प्लास्टिक सर्जरी और परमाणु की खोज भी भारत में हुई थी और नारद भारत के पहले पत्रकार थे।

दिनेश शर्मा ने बच्चों के सामने ज्ञान परोसा कि तकनीकी की दृष्टि से महाभारत काल और रामायण काल ज्यादा उन्नत था। उदाहरण देते हुए बताया, धृतराष्ट्र के पास एक लाइव टीवी था। जिसके जरिए वो अपने घर से कुरुक्षेत्र का हाल जान लेते थे।

खबर (दार) झरोखा

सरकार के चार साल, तर्क और तथ्यों के अचार साल हैं

रवीश कुमार

मोदी सरकार के चार साल पूरे होने के दिन भी पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़े हैं। 13 मई से 26 मई के बीच पेट्रोल के दाम में 3.86 रुपये और डीज़ल के दाम में 3.26 रुपये की वृद्धि हो गई है। कर्नाटक चुनाव ख़त्म होते ही अख़बारों ने लिख दिया था कि चार रुपये प्रति लीटर दाम बढ़ेंगे, करीब करीब यही हुआ है। यानी दाम बढ़ाने की तैयारी थी लेकिन अमित शाह ने बोल दिया कि सरकार घटाने पर प्लान बना रही है। एक दो दिन से ज़्यादा बीत गए मगर कोई प्लान सामने नहीं आया।

हम सब समझते हैं कि तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं मगर सरकार में बैठे मंत्री को ही बताना चाहिए कि विपक्ष में रहते हुए 35 रुपये प्रति लीटर तेल कैसे बिकवा रहे थे। आज के झूठ की माफी नहीं मांग सकते तो पुराने बोले गए झूठ की माफी मांग सकते हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया पर कुतर्कों को जाल बुना गया है, वह बताता है कि यह सरकार जनता की तर्क बुद्धि का कितना सम्मान करती है।

बिजनेस स्टैंडर्ड के शाइन जेकब की रिपोर्ट पढ़िए। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2022 तक हम तेल का आयात 10 फीसदी कम कर देंगे। इस वक्त तेल का आयात 16.4 फीसदी बढ़ चुका है। कहते कुछ है हो कुछ जाता है या फिर इन्हें पता नहीं होता कि करना क्या है और कहना क्या है।

सरकार आई तो खूब दावे किए गए कि कोयले के खदान के लाइसेंस दिए गए हैं। उनमें पारदर्शिता आई है। क्या आपको पता है कि कितने खदान चालू हुए और कितने चालू ही नहीं हुए। इसका कारण जानेंगे तो और दुख पहुंचेगा कि सरकार के कितने झूठ का पर्दाफाश होते देखें, इससे अच्छा है कि चलो भक्त ही बन जाया जाए, कम से कम सोचना तो नहीं पड़ेगा। हालत यह है कि दो हफ्ते में दो बार सरकार कोल इंडिया को लिख चुकी है कि कोयले का उत्पादन बढ़ाइये और बिजली कंपनियों को दीजिए क्योंकि गर्मी में मांग बढ़ गई है। क्या सरकार को पता नहीं था कि जब बिजली पहुंची है तो गर्मी हो या सर्दी, मांग भी बढ़ेगी। गर्मी का बहाना कर रही है मगर सितंबर से दिसंबर के बीच भी कोयले की आपूर्ति कम थी। कोयले की कमी से 2017 में भी बिजली के उत्पादन पर असर पड़ा था। उत्पादन घटा था।

रिटायर हो चुके लोगों को अब न्यू पेंशन स्कीम का झांसा समझ आ रहा है। 14-15 साल से चले आ रहे इस स्कीम के तहत जो रिटायर हो रहे हैं उन्हें पेंशन के नाम पर 1200-1300 रुपये मिल रहे हैं। इसके लिए यह लोग भी खुद ज़िम्मेदार हैं। मुद्दों को लेकर नहीं समझना, झांसे में आना, आलस्य करना, और अपना देखो, दूसरे का छोड़ो करते करते समय काट लेना। नतीजा यह है कि आज जब हाथ में 1300 रुपये देख रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। मोदी मोदी करें या राम राम करें।

EPFO प्रोविडेंट फंड की ब्याज़ दर पांच साल में सबसे कम हो गई है। 5 करोड़ लोगों को 2017-18 के लिए 8.55 प्रतिशत ब्याज़ ही मिलेगा। 2012-13 के बाद यह सबसे कम है।

पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बड़ौदा इन सब का घाटा देखिए। इनका घाटा इतिहास बना रहा है। आई डी बी आई का सकल एन पी ए 28 फीसदी हो गया है। एक बैंकर ने कहा कि सरकार जब दावा करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। निवेश हो रहा है तो फिर वही बता दे कि स्टील उद्योग क्यों संकट में हैं। क्यों स्टील उद्योग से एन पी ए हो रहा है। हम सामान्य लोग सरकार के फज़ीवाड़े को नहीं समझ पाते मगर बैंकर की एक लाइन से तस्वीर खींच जाती है। एक लक्ष्मी विलास बैंक है उसे भी 600 करोड़ का घाटा हुआ है।

बैंक का पूरा सिस्टम ध्वस्त है। बैंक कर्मी इतनी कम सैलरी में काम कर रहे हैं कि पूछिए मत। 17500 रुपये की सैलरी में कोई बैंक क्लर्क दिल्ली शहर में कैसे रह सकता है। कहीं भी इस सैलरी में कैसे रहता होगा। अब बैंकरों को ट्रांसफर का भय दिखा कर उनसे दूसरे काम कराए जा रहे हैं। सरकार को पता है कि बैंक समाप्त होने की स्थिति में है। इसलिए उन्हें कभी मुद्रा लोन के फज़ीवाड़े का टारगेट दो तो कभी अटल पेंशन योजना का। यही नहीं बैंक अब आधार कार्ड भी बनवा रहे हैं। इन सबके बाद भी बैंकरों की सैलरी नहीं बढ़ रही है। बैंकर रोज शाम को काम ख़त्म होने के बाद ब्रांचों के बाहर प्रदर्शन करते हैं। लाखों बैंकरों की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। उनके ये पांच साल कभी नहीं लौटेंगे। नौटबंदी जैसे फ्राड को वे देशसेवा समझ रहे थे। इसलिए ज़रूरी है कि नागरिक अपनी समझ का विस्तार करें। भक्ति तो कभी भी की जा सकती है।

वही हाल दो लाख ग्रामीण डाक सेवकों का है। इनकी सैलरी नहीं बढ़ी है। ये लोग 5000 रुपये में कैसे जीते होंगे। सरकार इन्हें हिन्दू ही समझ कर सैलरी दे दे या भक्त सरकार से कहें कि ये हिन्दू हैं और इन्हें तकलीफ है। 12 दिनों से हड़ताल पर हैं मगर कोई इनसे बात करने को तैयार नहीं। ग्रामीण डाक सेवकों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है।

कोबरा पोस्ट का स्टिंग देखिए। मैं स्टिंग को लेकर हमेशा दूरी रखता हूं मगर इसके तथ्यों की जांच तो होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ अनदेखी ही करते रहेंगे तो फिर ऐसे ख़तरों के लिए तैयार रहिए जिसकी कल्पना आपने नहीं की है। क्योंकि इनकी मार आप पर पड़ेगी जैसे लाखों बैंकरों पर पड़ रही है। स्टिंग से पता चलता है कि मोबाइल कंपनी पे टी एम कंपनी ने अपना डेटा सरकार को दिया है। यही बात अमरीका में सामने आई होती तो हंगामा मच गया होता। रविशंकर प्रसाद फेसबुक को तो ललकार रहे थे, क्या इस स्टिंग के बाद पेटीएम पर कुछ कर सकते हैं? आने वाले चुनाव में खेल बिग डेटा से होगा। उसकी तैयारी हो चुकी है। इस विषय को समझने वाले बहुत दिनों से बता रहे हैं। देखते हैं क्या हो रहा है।

मगर ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसके लिए सरकार जश्न मना सकती है? मेरे हिसाब से दो सेक्टर हैं। एक झूठ और दूसरा धर्मांधता। हर सरकार के दौर में एक राजनीतिक संस्कृति पनपती है। मोदी सरकार के दौर में झूठ नई सरकारी संस्कृति है। जब प्रधानमंत्री ही झूठ बोलते हैं तो दूसरे की क्या कहें। दूसरी संस्कृति है धर्मांधता की। भारतीय जनता पार्टी और आर एस एस से से इत्तफाक रखने वाले कई संगठन बनकर खड़े हो गए हैं जो काम तो इन्हीं के लिए करते हैं मगर अलग इसलिए हैं ताकि बदनामी इन पर न आएं।

नौकरी के फ्रंट पर यह सरकार फेल है। आप किसी युवा से पूछ लें जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है। रेलवे ने बड़े ज़ोर ज़ोर से एलान किया कि एक लाख भर्ती निकाली जा रही है। जबकि रेलवे में ढाई लाख वेकैंसी है। क्या आप जानते हैं कि दो महीने हो गए फार्म भरे, अभी तक इम्तहानों की तारीख नहीं निकली है। एम्स को लेकर प्रोपेगैंडा होता है, क्या आप जानते है कि 6 एम्स में नॉन टेक्निकल स्टाफ के 80 फीसदी पोस्ट खाली हैं। 20,000 से ज़्यादा। क्या मैं नौजवानों की नौकरी की बात कर, मोदी का विरोध कर रहा हूं। तो फिर आप बता दीजिए कि मोदी जी हैं किस लिए। उनके मंत्री हैं किस लिए। फिर नौजवान ही कह दें कि हमें नौकरी नहीं चाहिए। आप हमारी नौकरी की बात न करें। मैं नौकरी की बात छोड़ देता हूं।

सरकार के चार साल तर्क और तथ्यों के अचार साल हैं। सरकार ने इन सबका अचार डाल दिया है ताकि रोटी के साथ सब्ज़ी नहीं होगी तो आप इसी अचार से रोटी खा सकें। आपको जादू दिखाया जा रहा है, आप जादू देखिए।

लोकतन्त्र के द्रष्टा!

देश के धीमेपन से असंतुष्ट जवाहरलाल के सामने क्या यह विकल्प नहीं रहा होगा कि लोकतंत्र को एक तरफ रखकर कुछ साल चाबुक चलाया जाए, ताकि देश तेज दौड़कर एक बार सबके साथ आ सके? यदि वे चाबुक चलाते तो क्या एक नशीला उत्साह सारे देश में पैदा नहीं होता, जिसके रहते लोकतंत्र की हिमायत एक जनद्रोही हरकत नजर आती? यदि सरदार पटेल को स्वाधीनता के बाद 17 साल तक जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता और उनका पद मिला होता तो क्या वे माओ त्से तुंग या स्तालिन के भारतीय संस्करण नहीं हो जाते? सुकर्णो, नासर, टीटो, अंक्रूमा आदि ने अपनी लोकप्रियता का क्या किया? यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के अलावा कोई और प्रणाली होती तो वह भारत जैसे बेमेल देश को एक नहीं रख पाती। स्वराज के बारे में हम भारतीयों का हीनभाव ही तानाशाही को जन्म दे सकता था। उस नियति से हम बचे, इसका सारा श्रेय नेहरू को है।

- राजेंद्र माथुर